



Centre for Promotion of
Arts and Sciences

हम सब

त्रैमासिक न्यूज़लेटर

अंक संख्या 6 | अप्रैल-जून 2026 | तृतीय आयतन



मैतेरिया

इस अंक में

संपादक के डेस्क से

बी. पी. मंडल

विशेष लेख

'चाय की कहानी'

कविता

उद्धरण योग्य उद्धरण

"भगवान ने हमें याद दी कि दिसंबर में हमारे पास गुलाब हो सकते हैं।

जेम्स एम. बैरी

संपादक के डेस्क से

न्यूज़लेटर के इस अंक में, हमारे पास बीपी मंडल पर पहला लेख है। उन्हें द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। यह ज्ञात नहीं होगा कि वह बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, हालांकि थोड़े समय के लिए। लेख में, हम यहां बीपी मंडल की एक संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करते हैं।

दूसरा अनुच्छेद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का परिचय है। यह देश में किसी समुदाय के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर प्रकाश डालता है। अन्य बातों के अलावा, इस लेख में देश में पिछड़ी जातियों/वर्गों की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है।

अगला लेख 'चाय की कहानी' शीर्षक से श्री राहुल श्रीवास्तव का है। इसकी शुरुआत लगभग पांच हजार साल पहले चीन में चाय की पत्ती की खोज से होती है। इसके बाद यह अपनी आगे की यात्रा का लेखा-जोखा प्रदान करता है - जो पूरी दुनिया में एक बेहद लोकप्रिय गर्म पेय को जन्म देता है। लेख जानकारीपूर्ण और आकर्षक दोनों है।

हमारे न्यूज़लेटर के अंतिम आइटम के रूप में, हमारे पास श्रीमती लीला सिंह की एक कविता है जिसका शीर्षक है 'शरीर और आत्मा'। कविता वास्तव में बहुत मार्मिक है, और मुझे यकीन है कि पाठक इसे पढ़ना पसंद करेंगे।

अंत में, पहले की तरह, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप व्यापक पाठकों के लिए और परिवार और दोस्तों के साथ अपने लेख/कविता को साझा करने के लिए मुझे न्यूज़लेटर के लिए लघु लेख भेजें।

शरत कुमार

बिंधेश्वरी प्रसाद मंडल

(1918-1982)



बी.पी. मंडल आयोग की रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को पेश करते हुए

बी. पी. मंडल का नाम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग **के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है**। आयोग को आज 'मंडल आयोग' के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह इसके अध्यक्ष थे। यह रिपोर्ट दो वर्ष की संक्षिप्त अवधि में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह रिपोर्ट एक विद्वतापूर्ण कार्य है और भारतीय समाज के सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में इसके अध्यक्ष और इसके अन्य सदस्यों के जुनून को प्रदर्शित करती है।

बी. पी. मंडल बिहार के मधेपुरा जिले के एक जमींदार/जमींदार परिवार से आते थे। अपने उच्च वंश के बावजूद, उन्हें दरभंगा के राज हाई स्कूल के छात्रावास में रहने के दौरान जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि उच्च जाति के अन्य छात्रों के खाना खत्म करने के बाद ही उन्हें खाना परोसा गया। उन्होंने इस प्रणाली को अपमानजनक पाया और इसलिए विरोध किया। बाद में स्कूल ने इस प्रथा को बंद कर दिया।

बहुत बाद में 1965 में, जब वह बिहार विधान सभा के सदस्य थे और उन्हें पामा गांव की पिछड़ी जातियों के सदस्यों पर उच्च जातियों के सदस्यों के साथ-साथ पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पता चला, तो उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के बावजूद विधान सभा में इस मुद्दे को उठाया। जब पीड़ितों को मुआवजा देने की उनकी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और विपक्ष में शामिल हो गए। पिछड़ी जातियों के हितों को उठाने में उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर, जो तत्कालीन समाजवादी प्रकाश थे भारत में आंदोलन राम मनोहर लोहिया ने उन्हें बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) के नेता के रूप में नामित किया।

1967 के आम चुनावों के दौरान, वह लोकसभा के लिए चुने गए। उन्हें बिहार में गठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद की भी पेशकश की गई थी, जिसमें वे शामिल हो गए। इससे कुछ विवाद हुआ और उन्हें एसएसपी की सदस्यता से इस्तीफा देना

पड़ा। बाद में उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। तत्कालीन तरल राजनीतिक स्थिति और मौजूदा गठबंधन सरकार के पतन के परिणामस्वरूप, उन्होंने 1968 में विभिन्न दलों का एक नया गठबंधन बनाया और पचास दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने।

वह 1972 में फिर से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप, सर्वोदय नेता जय प्रकाश नारायण (जेपी) ने विधानसभा के सदस्यों को इस्तीफा देने का आह्वान किया। उनके आह्वान पर बीपी मंडल ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह एक बार फिर मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। जनता पार्टी के सत्ता में आने पर 1978 में उनकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आयोग ने दिसंबर 1980 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके अध्यक्ष द्वारा किए गए श्रमसाध्य प्रयासों को दर्शाता है।

आयोग की सिफारिशों के बाद के कार्यान्वयन ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से भारतीय समाज के सामाजिक पुनर्गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि, बीपी मंडल अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन को देखने के लिए जीवित नहीं थे क्योंकि 1982 में उनका निधन हो गया था।

विशेष लेख

दूसरा पिछड़ा आयोग - एक परिचय

शरत कुमार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में संक्षेप में इस प्रकार लिखा है, 'राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो वह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उन कठिनाइयों की जांच करने के लिए जिनके तहत वे श्रम करते हैं और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनमें सुधार करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए उपयुक्त समझे। स्थिति'। गौरतलब है कि संविधान में अनुच्छेद 340 में 'जाति' के बजाय 'वर्ग' शब्द का उल्लेख किया गया है।

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मार्च 1979 में अपना काम शुरू किया और दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के अन्य सदस्यों में आरआर भोले, दीवान मोहन लाल, के. सुब्रमण्यम और एलआर नाइक शामिल थे। श्री एमएस गिल आयोग के सचिव थे।

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान इस प्रकार की: (क) पारंपरिक हिंदू समाज में जिनकी सामाजिक स्थिति कम थी, (ख) जिनके पास सामान्य शिक्षा की कमी थी और (ग) जिनका सरकारी सेवा, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में अपर्याप्त या कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। आयोग ने 2,399 जातियों को 'पिछड़े' के रूप में पहचाना, जिनमें से 837 "सबसे पिछड़े" हैं।

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपनी सिफारिशों में उन्होंने व्यापक भूमि सुधार, भूदान आंदोलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के अलावा सरकारी सेवा में नौकरियों के आरक्षण जैसे उपायों की सिफारिश की। गौरतलब है कि आयोग के कई सदस्य पिछड़ेपन के आधार के रूप में 'जाति' को शामिल करने का विरोध कर रहे थे।

इसके अलावा, राष्ट्रपति (डॉ. राजेंद्र प्रसाद) को भेजे अपने अग्रेषण पत्र में, काका कालेलकर ने कहा:

'यह आश्चर्य होने के बाद कि हिंदुओं में उच्च जाति को उस उपेक्षा के लिए प्रायश्चित्त करना होगा जिसकी वे "निम्न वर्गों" के प्रति दोषी थे, मैं सरकार को यह सिफारिश करने के लिए तैयार था कि सभी सामाजिक सहायता केवल पिछड़े वर्गों को दी जानी चाहिए और यहां तक कि उच्च वर्गों के बीच गरीब और योग्य लोगों को भी विशेष सहायता के लाभ से सुरक्षित रूप से बाहर रखा जा सकता है।'

उन्होंने आगे कहा:

उन्होंने कहा, 'जब रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तभी मैंने नए सिरे से सोचना शुरू किया और पाया कि पिछड़ेपन से जाति के अलावा किसी आधार पर या कुछ आधार पर निपटा जा सकता है।'

आयोग की सिफारिशों के बारे में उन्होंने कहा:

'इसने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि हमने जो उपाय सुझाए थे, वे उस बुराई से भी बदतर थे जिसका हम मुकाबला करने वाले थे।'

सरकार में नौकरियों के आरक्षण के मुद्दे के बारे में उन्होंने तर्क दिया:

उन्होंने कहा, 'मैं निश्चित रूप से किसी भी समुदाय के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के खिलाफ हूं, क्योंकि यह सेवाएं नौकरों के लिए नहीं हैं, बल्कि वे पूरे समाज की सेवा के लिए हैं।'

यद्यपि सरकार ने आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में संसद को सूचित किया, फिर भी इसकी सिफारिशों पर कोई चर्चा नहीं हुई। संसद में रखे गए एक ज्ञापन के माध्यम से, सरकार ने अपने सदस्यों के बीच दृष्टिकोण की भिन्नता पर प्रकाश डाला और कहा:

उन्होंने कहा, 'इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समतावादी समाज की ओर हमारी प्रगति में जाति व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि, निर्दिष्ट जातियों को "पिछड़े" के रूप में मान्यता देने से जाति के आधार पर मौजूदा भेदों को बनाए रखने का काम किया जा सकता है।'

भारत सरकार ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर केंद्र सरकार की सेवा में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर भी, यह स्पष्ट किया गया है कि 'भले ही केंद्र सरकार अनुच्छेद 338 (3) के तहत लोगों के कुछ समूहों को 'अन्य पिछड़ा वर्गों' से संबंधित के रूप में निर्दिष्ट करती है, फिर भी यह प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए अपनी सूची तैयार करने के लिए खुली होगी।

उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकती है, जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए उपर्युक्त स्पष्टीकरण के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पात्र समुदायों को सरकारी सेवा में नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियमों में तेजी आई है, हालांकि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई हैं।

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट में काका कालेलकर की दुर्दशा को दोहराने में भले ही उन्होंने काफी उदारता दिखाई, लेकिन इसके अध्यक्ष (बी. पी. मंडल) ने उनके तर्कों का प्रतिवाद करते हुए कहा, 'लेकिन, उद्देश्य कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, यह संविधान के अनुच्छेद 340 की भावना के अनुरूप नहीं है जिसके तहत आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 15 (4) और 340 (1) दोनों "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों" का स्पष्ट संदर्भ देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन अनुच्छेदों में आर्थिक पिछड़ेपन के किसी भी संदर्भ को छोड़ दिया गया है।

विचारार्थ विषयों के अनुसार, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने किसी समुदाय को 'पिछड़ी जाति/वर्ग' के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित तीन व्यापक मानदंड तैयार किए हैं:

सामाजिक: (क) निम्न जाति, जिसे सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, (ख) लोगों की एक जाति या समुदाय जो मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर निर्भर है, (ग) एक जाति जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में इसकी 10 प्रतिशत महिलाएं - 17 वर्ष और उससे कम उम्र में शादी कर रही हैं और (घ) एक ऐसी जाति जिसमें राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी है।

शैक्षिक: (क) जाति/समुदाय जिसमें 5-15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक स्कूल नहीं जा रहे हैं, (ख) 5-15 वर्ष के आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या वाले जाति/समुदाय की संख्या राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक है और (ग) जाति/समुदाय जिसमें मैट्रिक का अनुपात है, यह राज्य के औसत से 25 प्रतिशत कम है।

आर्थिक: (क) जाति/समुदाय, जहां संपत्ति का औसत मूल्य राज्य के औसत से 25 प्रतिशत कम है, (ख) जाति/समुदाय, जहां कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक है, (ग) एक ऐसी बस्ती में रहने वाली जाति/समुदाय जहां पीने के पानी का स्रोत आधा किलोमीटर दूर है, (घ) राज्य औसत से अधिक उपभोग ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या वाले जाति/समुदाय की संख्या 25 प्रतिशत है।

इसके अलावा, आयोग ने 'सामाजिक' मानदंड के तहत शामिल प्रत्येक मानदंड के लिए तीन (3) बिंदुओं का वेटेज संलग्न किया, 'शैक्षिक' मानदंड के तहत शामिल प्रत्येक बिंदु के लिए दो (2) अंक का वेटेज और प्रत्येक 'आर्थिक' मानदंड के लिए एक (1) अंक का वेटेज संलग्न किया। इसने **समग्र स्कोर** को 22 (12+6+4) के बराबर बना दिया, जिसमें तीनों मानदंड शामिल थे।

आयोग के अनुसार, जो भी जाति/समुदाय इस समग्र स्कोर (22) का 50 प्रतिशत स्कोर करता है, यानी ग्यारह (11) अंक या उससे अधिक प्राप्त करता है, उसे 'पिछड़ी जाति/समुदाय' के रूप में घोषित किया जाना था।

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले 1961 की जनसंख्या जनगणना के दौरान जातियों की गणना को शामिल करने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 1981 की जनगणना के दौरान जातियों की गणना करने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने इसे एक बार फिर खारिज कर दिया था। किसी भी हालिया डेटा के अभाव में, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाति गणना पर उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग किया, जो पहली बार 1891 में और बाद में 1931 में किए गए थे। इसके बाद उन्होंने 1979/1980 के दौरान देश में जाति वितरण के सबसे संभावित परिदृश्य पर पहुंचने के लिए विभिन्न जाति समूहों की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति का अनुमान लगाया।

तदनुसार, उन्होंने 1979/1980 के दौरान देश में जाति वितरण पर निम्नलिखित अनुमान प्रदान किए: (1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति [22.56%], (2) अगड़ी हिंदू जातियाँ [17.58%], (3) गैर-हिंदू समुदाय [16.06%]। इस प्रकार (4) पिछड़ी हिंदू जातियों की शेष आबादी [43.7%] या [100% - 56.30%] थी। इसके अलावा, उनकी गणना के अनुसार, (5) पिछड़ी गैर-हिंदू जातियों ने कुल आबादी का गठन किया [8.4%]। इस वितरण के आधार पर, **आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि पिछड़ी जातियाँ देश की कुल जनसंख्या का 52% (43.7 + 8.4 = 52.1) हैं।**

आयोग ने कहा कि पिछड़ा वर्ग/जातियों को सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़ा जाति/वर्ग के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के संबंध में भी इसी तरह का कोटा तय किया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कि नौकरियों में आरक्षण के संबंध में अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से ही 22.6 प्रतिशत का आरक्षण मौजूद है, आयोग ने **पिछड़ी जातियों/वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।**

समापन टिप्पणियाँ

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को एक दशक बाद इसके अध्यक्ष के निधन के बाद लागू किया गया था। इस संबंध में विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं को न्यायालयों में चुनौती दी गई थी और इसे प्रभावी बनाने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन पेश किए जाने थे। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नौकरियों में आरक्षण को एक उपकरण के रूप में बनाने के बारे में संदेह था। यह बात प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कही है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पंक्तियों को पढ़ने से पता चलता है कि इस संदेह को दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने भी कम मात्रा में साझा नहीं किया था। लेकिन उन्होंने फिर भी इसके सीमित मूल्य के लिए इसका समर्थन किया। अंतिम विश्लेषण में, यह देश का समग्र विकास है जो सभी के उत्थान की कुंजी रखता है।

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था कि नौकरियों का आरक्षण हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। यदि स्थिति में सुधार होता है, तो एक विशेष जाति/समुदाय अब पिछड़ों की सूची में नहीं रहेगा। इसलिए, इसे आरक्षण के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग सरकार को निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करने का अधिदेश देता है। इस प्रकार, यदि तेजी से आर्थिक प्रगति होती है और समाज में दृष्टिकोण की आधुनिकता होती है, तो हम आशा कर सकते हैं कि 'पिछड़ापन' जैसा कि हम आज पहचानते हैं, 2047 तक अस्तित्व में नहीं रहेगा।

इसके अलावा, देश को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के संबंध में दो तात्कालिक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक फरवरी 2027 में जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ **देश में विभिन्न जातियों की** गणना से संबंधित है। इस संदर्भ में, "प्रश्नावली" का उचित डिजाइन - आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए - अत्यंत महत्व प्राप्त करता है। दूसरा संबंधित मुद्दा किसी भी समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के मानदंडों से संबंधित है। इसलिए, हम या तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा विकसित मानदंडों के साथ रह सकते हैं या पूरी तरह से मानदंडों का एक नया सेट विकसित कर सकते हैं। पहले से ही आशंकाएं हैं कि जनसंख्या जनगणना (2027) देश में वास्तविक जाति वितरण के संबंध में अप्रत्याशित परिणाम ला सकती है।

चाय की कहानी

राहुल श्रीवास्तव*



चीन के सम्राट शेन नुंग एक दार्शनिक थे और हर्बल चिकित्सा में रुचि रखते थे। किंवदंती के अनुसार, एक बार जब शेन नुंग अपने बगीचे में बैठे थे और गर्म पानी का कटोरा पी रहे थे, तो हवा का एक झोंका चला और पास के एक पौधे के कुछ पत्ते उसके शाही कटोरे में गिर गए। सम्राट ने सुगंध को सूँघा, इस नई सुगंध पर खुशी से अपना शाही सिर हिलाया और गिरे हुए पत्ते के स्वाद वाले गर्म पानी को पी लिया। चाय पत्ती की इस खोज की तारीख 2737 ईसा पूर्व मानी जाती है।

चाय को पहले एक औषधीय जड़ी बूटी माना जाता था और इसे हरी अनुपचारित पत्तियों से संक्रमित किया जाता था। यह ज्यादातर लोगों के लिए यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त रूप से खराब हो गया होगा कि यह अपने औषधीय मूल्य के कारण उन्हें बहुत अच्छा कर रहा था। बाद में, चीनियों ने पाया कि एक बेहतर पेय संभव है यदि पत्तियों को मुरझाने दिया जाए और फिर संक्रमित होने से पहले नियंत्रित गर्मी के संपर्क में आने से सुखाया जाए। एक बार यह हो जाने के बाद, चाय लोकप्रियता की राह पर चल पड़ी।

एक वैश्विक पेय के रूप में चाय

कुछ दशक पहले तक ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा चाय पीने वाला देश था। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1664 में चीनी चाय के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया था। ब्रिटिश अभिजात वर्ग द्वारा संचालित, इसकी मांग आसमान छू गई। अंग्रेजों के लिए, गर्म 'कप्पा' एक पेय से कहीं अधिक है। 1760 में, ब्रिटिश बाजार में बेची जाने वाली चाय सिर्फ एक मिलियन पाउंड से कम थी। 1770 तक, एक दशक बाद, यह नौ मिलियन पाउंड तक बढ़ गया था। इसलिए सरकार ने मांग को कम करने के लिए 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है।

इस समय तक, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भी चाय के लिए एक स्वाद विकसित कर लिया था। प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी (1773) ने इतिहास की दिशा बदल दी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटेन से अमेरिका को चाय के पुनः निर्यात पर एक विरोध था। जैसे, जब तक चाय बोस्टन के बंदरगाहों पर पहुंची, तब तक चाय की कीमत दोगुनी हो गई। इसके विरोध में ईस्ट

इंडिया कंपनी की 342 चाय के पेटे जहाज से समुद्र में फेंक दिए गए। इसने युद्ध को जन्म दिया जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन से अमेरिका की स्वतंत्रता (1776) हुई!

हाल के वर्षों में, हालांकि, ब्रिटेन को भारत ने बदल दिया है, जिसने किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक चाय पीना शुरू कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण चाय पीने वाले देश रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, सूडान, मिस्र, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। आज दुनिया की लगभग आधी आबादी चाय का सेवन करती है।

यूरोपीय लोगों का पहले मानना था कि बोहिया जैसी चीनी **काली चाय** और सिंगलो और हाइसन जैसी हरी चाय अलग-अलग पौधों से आती है। जब वे भारत में चाय उगाने की संभावना तलाश रहे थे तभी उन्हें एहसास हुआ कि चाय के पौधे की केवल एक ही प्रजाति है, **कैमेलिया साइनेंसिस**। उन्हें यह भी पता चला कि अंतर *खेती* और *उपचार* में है। काली चाय को पहले किण्वित किया जाता है और फिर गर्मी से निकाल दिया जाता है या सुखाया जाता है, जबकि हरी चाय को बिना किण्वित किया जाता है।

भारत में चाय

चाय धीरे-धीरे भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), हिमालय की तलहटी में, और आगे पूर्व की ओर डुवर्स, दक्षिण भारत में नीलगिरी और चटगांव और सिलहट के रूप में जाना जाता है, जो अब बांग्लादेश है। भारत के उत्तर-पश्चिम में कांगड़ा घाटी और देहरादून में भी छोटे-छोटे बगीचे बन गए।

दार्जिलिंग, हिमालय में एक हिल स्टेशन, 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया की बेहतरीन चाय का उत्पादन करता है जिसे अक्सर '**चाय की शैपेन**' कहा जाता है। चाय 6500 फीट तक की विभिन्न ऊंचाई पर उगाई जाती है, हालांकि औसत ऊंचाई 3000 से 4000 फीट के बीच होती है। उत्तर-पश्चिम भारत में भी चाय की खेती हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी राज्य में कांगड़ा घाटी में की जाती है, जो कश्मीर से सटे हुए है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी ढलानों, नीलगिरि पहाड़ियों, कन्नन देवन की ऊंची श्रृंखला, वायनाड और दक्षिणी केरल में भी चाय उगाई जाती है।



यह बड़ी मुश्किल से था कि हाथियों और अन्य जंगली जानवरों से भरे घने जंगलों के बगल में चाय के बागान खोले गए थे। चाय की नीलामी 1861 में कलकत्ता में शुरू हुई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से, अधिकांश ब्रिटिश कंपनियां भारतीयों को बेच दी गई हैं। पिछले कई दशकों में उत्पादन तेज गति से बढ़ रहा है, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है।

1900 में भारत का चाय उत्पादन छोटा था, यह 1930 में बढ़कर 177 मिलियन किलोग्राम हो गया, 1980 में 577 मिलियन किलोग्राम हो गया, 1995 में 750 मिलियन किलोग्राम हो गया। देश में चाय का उत्पादन 1100-1200 मिलियन किलोग्राम तक चला गया 2025. लंबे समय से देश के लिए प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक। उच्च उत्पादन के बावजूद, देश के भीतर चाय की अधिक खपत के कारण हाल के वर्षों में निर्यात में उसी अनुपात

में वृद्धि नहीं हुई है। यह केवल मध्यम वर्ग के भारतीयों के बीच उच्च समृद्धि को दर्शाता है। **ब्रुक बॉन्ड इंडिया, लिफ्टन इंडिया** और **टाटा टी** जैसी प्रमुख पैकेज्ड चाय कंपनियों के बढ़ते नेटवर्क ने शहरी क्षेत्रों से बढ़ते ग्रामीण बाजारों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है।

वास्तव में, घरेलू खपत भारतीय चाय उत्पादकों के लिए एक मूल्यवान समर्थन साबित हुई है। विश्व बाजार में अधिक आपूर्ति की अवधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से गिरावट आती है और यह सामान्य अवसाद की ओर ले जाता है। बड़ा आंतरिक बाजार भारतीय उत्पादकों को इस तरह की अंतरराष्ट्रीय मंदी के खिलाफ एक सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक बाजार के इस स्थिर समर्थन के बिना, भारतीय उत्पादन अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता था।

चाय की खेती और प्रकार

चाय या 'कैमेलिया साइनेंसिस' कई देशों में उगाया जाने वाला एक कठोर फूल, सदाबहार पौधा है। इसे जलवायु की एक विस्तृत श्रृंखला में उगाया जा सकता है। हालांकि, स्वस्थ विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता बहुत अधिक वर्षा है। यह गर्मी और उमस के जंगल के वातावरण में सबसे अच्छा फलता-फूलता है। लेकिन इससे बेहतर गुणवत्ता वाली चाय प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। मिट्टी, पहलू, वर्षा, ऊंचाई और निर्माण सभी कारक हैं जो चाय को सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं।

चाय के तीन मुख्य प्रकार हैं, लेकिन वे सभी एक ही पौधे से आते हैं, और उनका अंतर निर्माण में से एक है, न कि खेती का। चाय का बड़ा हिस्सा ब्लैक टी के रूप में जाना जाता है। यह एक पूर्ण किण्वन प्रक्रिया से गुजरता है। **ग्रीन टी** बिना किण्वित होती है; पत्तियां किसी भी ऑक्सीकरण से नहीं गुजरती हैं। **ऊलोंग चाय** अर्ध-किण्वित या अर्ध-ऑक्सीकृत होती है। यह ताइवान की एक विशेषता है और इसमें काली और हरी चाय दोनों की कुछ विशेषताएं हैं। सारी चाय हाथ से तोड़ी जाती है क्योंकि यह एक नाजुक और कुशल ऑपरेशन है। मशीन प्लकिंग लोकप्रिय है जहां श्रमिकों की कमी है।

विपणन और व्यापार

बगीचों से, चाय को चेस्ट/बैग में पैक किया जाता है और कोलकाता, गुवाहाटी, केरल में कोचीन और नीलगिरी पर्वत में कुन्नूर में नीलामी केंद्रों में भेजा जाता है। चाय एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाली वस्तु है। पैकेट चाय कंपनियों (और उपभोक्ता द्वारा) द्वारा भुगतान की गई कीमत मूल रूप से दुनिया की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है, दोनों पूरी तरह से चाय और अलग-अलग प्रकार और गुणों की चाय की। चाय एक खराब होने वाली वस्तु है और इसे लंबे समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। नीलामी में थोक में चाय खरीदने वाले कॉर्पोरेट खरीदारों के लिए, अगला चरण प्रत्येक मिश्रण की लगातार गुणवत्ता और स्वाद बनाए रखने के लिए विभिन्न चाय का सम्मिश्रण है।

बदले में, चाय का विपणन दो चीजों का मतलब हो सकता है। पहला, चाय बागानों से चाय का थोक में नीलामी के माध्यम से या निजी बिक्री के माध्यम से निपटान किया जाता है। इसके बाद, थोक और खुदरा नेटवर्कों के माध्यम से उपभोक्ताओं को चाय के ब्रांडेड पैकेज्ड रूप में विपणन किया जाएगा।

हमारे दैनिक जीवन में चाय

चाय आज हमारी जीवनशैली का अभिन्न अंग बन गई है। हम अपने दिन की शुरुआत सुबह की चाय से करते हैं और दिन भर के लंबे काम के बाद शाम की चाय की प्रतीक्षा करते हैं। हम परिवार और दोस्तों की संगति में चाय का आनंद लेते हैं। यह हमारी यात्रा में हमारा निरंतर साथी है; हर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले को अपनी 'चाय गरम, गरम चाय' में हम सबका स्वागत करने और लुभाने वाले को किसे याद नहीं होगा!



तस्वीर में:

राहुल श्रीवास्तव, राजदूत रॉन मल्का, उनकी पत्नी और
लेखक की पत्नी प्रतिभा श्रीवास्तव

- राहुल श्रीवास्तव एक M.Sc (कृषि) हैं। वह पूर्व में जार्डिन हेंडरसन लिमिटेड के निदेशक थे और बाद में गोपाल कृष्णा टी कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में काम किया। इन दोनों कंपनियों के असम में अपने चाय बागान हैं।

'शरीर और आत्मा - एक प्रवचन'



रुको, रुको हे आत्मा!
तुम क्यों भाग रहे हो,
मुझे अकेला छोड़
असहाय, बेजान दुखी?

इतने सालों के लिए,
हम साथ रहते हैं,
मैंने तुम्हें अपने अंदर रखा,
एक मंदिर में एक देवता के रूप में।

मैंने आपके लिए क्या नहीं किया?
सरल या कठिन
आपने मुझे जो भी करने के लिए कहा।

अब तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो,
इस असहाय स्थिति में?
आपने क्या कहा?
मैं नश्वर हूँ और तुम अमर हो!

तो, तुम मुझे फेंकने जा रहे हो,
एक पुराने चीर की तरह,
और तुम सजाने जा रहे हो,
एक नई पोशाक! क्या दंभ!

तुम कितने धोखेबाज हो!
कितना स्वार्थी!
लेकिन ... अच्छी तरह से मेरी सुनो!
मेरे बिना तुम्हारा क्या महत्व है?

क्या आप इन बच्चों के लिए खाना बना सकते हैं?
क्या आप बीमार आदमी की देखभाल कर सकते हैं,
एक कोने में लेटा हुआ, केवल देख रहा है!
क्या आप आंखों से आंसू पोछ सकते हैं?

कोई आत्मा नहीं! नहीं!
तुम किसी के काम के नहीं हो,
तुम अर्थहीन हो!
यह आपको हैप्पी अनलिमिटेड बना सकता है,
यह आपको हैप्पी अनलिमिटेड बना सकता है!

तुम किसी के काम के नहीं हो,
और फिर भी...
हर कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है
तुम जाओ और एक नए शरीर में जाओ!

जिस शरीर में तुम रुके थे, उसे त्याग दिया जाता है,
सड़े हुए आलू की तरह,
जला दिया जाना या दफनाया जाना।

लेकिन
क्या आप अधिक महत्वपूर्ण हैं
मुझसे ज्यादा?
फिर इन दीवारों को देखो,
वहाँ सभी तस्वीरें!
यह मैं हूँ, हे आत्मा!
यह मैं हूँ, शरीर !!

लीला सिंह